जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

हिण्डौन सिटी

Rashtradoot

फोनः- 230200, 230400 फैक्सः- 07469-230600 वर्षः 17 संख्याः 189 प्रभात हिण्डौन सिटी, बुधवार 14 मई, 2025 पो. रजि.SWM-RJ-6069/2017-18 पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 रु.

भाजपा ग्यारह दिन की तिरंगा यात्रा निकालेगी

13 मई से 23 मई तक देशभर में चलने वाली इस यात्रा में पार्टी के प्रमुख नेता व कार्यकर्ता तिरंगा झण्डा लेकर चलेंगे, तथा ऑपरेशन ''सिन्दूर'' की सफलता का जश्न मनायेंगे सड़कों पर

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 13 मई। भाजपा ने ''ऑपरेशन सिंदूर'' की सफलता को ''अपना बनाने'' के लिए, आज ग्यारह दिवसीय ''तिरंगा यात्रा'' की शुरुआत की, लेकिन पार्टी के इस अभियान में विजय का स्वर गायब नजर आया और इसके दो मुख्य कारण हैं:

पहला, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्धिवराम को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के इस दावे पर सरकार की अपर्याप्त प्रतिक्रिया कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्धविराम का यह समझौता उन्होंने करवाया था और दूसरा, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का यह दावा कि भारत और पाकिस्तान किसी तटस्थ स्थान पर कश्मीर समेत, लंबित मुद्दों को सुलझाने के लिए बैठक करेंगे।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कल राष्ट्र को संबोधित करते हुए ट्रंप के दावे का परोक्ष जवाब दिया और कहा कि भारत पाकिस्तान से पीओके और आतंकवाद के अलावा अन्य किसी मुद्दे पर बात नहीं करेगा। हालांकि, रणनीतिक विशेषज्ञ

- **पर, पार्टी का यह अभियान अभी जोर नहीं पकड़ पाया है, क्योंकि, सरकार अभी तक पूर्णतया संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाई, ट्रम्प की इस गर्वोक्ति का कि उन्होंने ''सीज़ फायर'' करवाई है, भारत-पाकिस्तान के बीच।**
- **हालांकि प्र.मंत्री मोदी ने इस गर्वोक्ति का थोड़ा-बहुत जवाब तो दिया, यह कहकर कि, भारत पाकिस्तान से केवल आतंकवाद व पाक अधिकृत कश्मीर पर ही बात करेगा।**
- **थोड़ा इस बात से भाजपा का जोश ठण्डा पड़ा कि ट्रम्प ने यह भी दावा किया कि, उन्होंने दोनों देशों को धमकी दी, कि अमेरिका दोनों देशों से व्यापार नहीं करेगा, अगर वह ''सीज़ फायर'' पर राजी नहीं होते हैं।**
- **विदेश मंत्रालय ने इस बात का भी खण्डन किया, यह कह कर कि भारत व अमेरिका के बीच वार्ता में ''व्यापार'' (ट्रेड) पर कोई बात नहीं हुई।**
- **''सीज़ फायर'' के बाद, भाजपा की पहली प्रेस कांफ्रेंस में सम्बित पात्रा ने यह दावा करके, कि पाकिस्तान ने इस लड़ाई में मिसाइल, एयर बेस तथा 100 आतंकवादी गंवाए, भाजपा की ''तिरंगा यात्रा'' में जोश भरने का प्रयास जरूर किया।**

ब्रह्मा चेल्लानी का कहना है कि कश्मीर का मुद्दा उठाये बिना पाकिस्तान से पीओके और आतंकवाद पर बातचीत करना असंभव होगा।

आज मीडिया को संबोधित करते हुए, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रंधीर जायसवाल ने ट्रंप के एक और दावे को खारिज किया। ट्रंप ने कहा था कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान को चेतावनी दी थी कि अगर वे युद्धिवराम पर सहमत नहीं होंगे तो अमेरिका उनके साथ व्यापार नहीं करेगा। जायसवाल ने कहा कि भारत और अमेरिका के नेताओं के बीच हुई बातचीत में व्यापार का कोई जिक्र नहीं था।

रविवार को भाजपा प्रमुख जे.पी. नड्डा के आवास पर हुई पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक में विपक्ष द्वारा उठाए गए सवालों-जैसे अमेरिका की भूमिका और कश्मीर मुद्दे पर किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता की संभावना पर चर्चा की गई। बैठक में इन प्रश्नों के जवाबों पर भी चर्चा हुई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी सहित, विपक्षी नेता इन मुद्दों पर सरकार से स्पष्टीकरण देने के लिए सर्वदलीय

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

केन्द्र के आश्वासन के बाद भी देहरादून में दहगाह तोड़ी

नई दिल्ली, 13 मई। वक्फ संशोधन कानून को लेकर केन्द्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में आश्वासन दिए जाने के बावजूद, उत्तराखंड में वक्फ संपत्ति के रूप में अधिसूचित हजरत कमाल शाह दरगाह को तोड़े जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की बेंच ने उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद बर्धन, देहरादून के जिला मजिस्ट्रेट सविन बंसल, देहरादून के सिटी मजिस्ट्रेट प्रत्यूष सिंह और देहरादून नगर आयुक्त नमामि बंसल को

- **सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखण्ड सरकार व देहरादून जिला प्रशासन को एक अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए नोटिस जारी किया।**

अवमानना याचिका पर नोटिस जारी किया है। मामले की सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि सरकार के आश्वासन के बावजूद, 25 अप्रेल सुबह बिना किसी सूचना के दरगाह को गिरा दिया गया। कोर्ट ने सरकार ने आश्वासन के उल्लंघन पर चिंता जताई है।

17 अप्रैल को वक्फ बोर्ड संशोधित कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान, केन्द्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को यह आश्वासन दिया

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

भाजपा को शीघ्र ही जवाब ढूंढ़ना पड़ेगा इन सवालों का

जब भारत, ''मिलिटरिली'' पाकिस्तान पर हावी था, विशेषकर ''हवाई युद्ध'' में, फिर, भारत ने ''क्यों'' स्वीकार किया, अमेरिका का ''आदेश'' सीज़ फायर के लिए

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 13 मई। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस समय कटघरे में खड़े हैं। उन्हें अपनी ही पार्टी, आरएसएस, अपने प्रमुख जनाधार मध्यम वर्ग, विपक्ष और सबसे महत्वपूर्ण, सशस्त्र बलों के भीतर से कई सवालों का सामना करना पड़ रहा है।

निराशा है, आक्रोश है और यह भावना भी है कि जिस तरह से नरेन्द्र मोदी, डॉनल्ड ट्रंप के पाकिस्तान के खिलाफ युद्धविराम के निर्देश के आगे झुक गए, वह एक तरह का विश्वासघात था, जबकि सैन्य दृष्टि से भारत युद्ध में बहुत आगे था और अपनी श्रेष्ठ वायु शक्ति के साथ पाकिस्तान पर भारी प्रहार कर रहा था।

यह लगभग सभी के लिए एक झटका था।

प्रधानमंत्री कैसे और क्यों यह मान गए कि युद्धविराम की घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप करें, वह भी शाम 5 बजे, जबकि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्धविराम का समझौता तो पहले ही तय हो चुका था, जब पाकिस्तान के डीजीएमओ ने दोपहर 3:30 बजे भारत के डीजीएमओ को फोन किया।

- **दूसरा सवाल है, क्या भाजपा सरकार ने ट्रम्प को अनुमति/सहमति दे दी थी शाम को पांच बजे, यह घोषणा करने के लिए कि भारत पाकिस्तान में ''सीज़ फायर'' हो गया है, उन्होंने सीज़ फायर करवा दिया है। जबकि डेढ़ घण्टे पहले ही, दोनों देशों के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिटरी ऑपरेशन ने आपस में बात करके ''सीज़ फायर'' की सहमति बना ली थी।**
- **तीसरा सवाल है, दो देशों के बीच चल रहे मुद्दे में तीसरी पार्टी को भूमिका निभाने का मौका कैसे मिल गया?**
- **चौथा, सवाल है, भारत की ''डिप्लोमैसी'' इतनी कमज़ोर कैसे हो गई कि वह पाकिस्तान को आई.एम.एफ. का पैकेज देने से नहीं रोक सकी। और यहां तक कि पैकेज में कुछ विलम्ब तक नहीं करा सकी, यह कहकर कि अभी दोनों देशों के बीच युद्ध चल रहा है, तथा यह आशंका है, कि वित्तीय पैकेज का उपयोग हथियार खरीदने में किया जाएगा।**

भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय मामला अचानक त्रिपक्षीय कैसे हो गया, जिसमें अमेरिका ने पूरी स्थिति की दिशा तय कर दी?

भारत की कूटनीति तब विफल हुई, जब वह पाकिस्तान के लिए आईएमएफ राहत पैकेज को रोक नहीं सका, यहाँ तक कि युद्ध की स्थिति में भी, वह इसे मात्र एक महीने के लिए भी टाल नहीं पाया।

पहलगाम में निर्दोष पर्यटकों पर हमला करने वाले आतंकवादी अब भी खुलेआम घूम रहे हैं, उन्हें न तो पकड़ा गया है और न ही मारा गया।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

शशि थरूर किसके प्रवक्ता हैं, कांग्रेस के या मोदी के?

- डॉ. सतीश मिश्रा -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -

नई दिल्ली, 13 मई। राजनैतिक गलियारों में इन दिनों ये चर्चाएं और अफवाहें सुनने को मिल रही हैं कि क्या कांग्रेस सांसद शशि थरूर भाजपा में पहुंच गये है, क्योंकि ''ऑपरेशन सिंदूर'' के बाद, वे नरेन्द्र मोदी सरकार के अनौपचारिक प्रवक्ता की तरह काम करते नजर आ रहे हैं। सर्वविदित है कि ऑपरेशन सिंदूर के अन्तर्गत, भारतीय सशस्त्र सेनाओं ने 7 मई को पड़ोसी देश पाकिस्तान के आतंकी शिविरों पर सटीक स्ट्राइक की थी।

ये अफवाहें उस समय विश्वसनीय लगने लगीं, जब तिरुवन्तपुरम सांसद थरूर ने उस मुद्दे का उल्लेख किया, जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार शाम को राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में अनकहा छोड़ दिया था-अर्थात दोनों न्यूक्लियर पड़ोसियों पर युद्धविराम के लिए दबाव डालने की अमेरिका की भूमिका का मुद्दा।

सोमवार शाम को मोदी के राष्ट्र के नाम संदेश से पहले, थरूर ने जाने-माने पत्रकार करण थापर को दिये गये एक इंटरव्यू में जोर देते हुए कहा कि अमेरिकन राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प को शर्मिन्दगी उठानी पड़ेगी, क्योंकि भारत, पाकिस्तान के साथ गनपॉइन्ट पर तो समझौता करने से रहा। और ट्रंप तथा अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने यह बात कही भी है।

आश्चर्य की बात यह है कि थरूर ने वह बात कह दी, जिसे कहने की हिम्मत प्रधानमंत्री मोदी नहीं जुटा सके, जिस बात को उनकी सरकार का कोई मंत्री नहीं कह पाया, और यहां तक कि विदेश मंत्रालय के अधिकृत प्रवक्ता भी जिसे कहने का साहस नहीं कर सके।

थरूर, जो विदेशी मामलों से संबंधित संसद की स्थायी समिति के अध्यक्ष है, ने थापर के एक प्रश्न के उत्तर में कहा, ''हम भारत की विदेश नीति के सम्पूर्ण सिद्धान्त को उनके सिर पर नहीं उड़ेल रहे हैं। हम अपने सिर पर रखी बंदूक की नौंक के डर से भी समझौता करने वाले नहीं हैं।

शनिवार की शाम को राष्ट्रपति ट्रंप ने इस बात का तीन बार श्रेय लिया कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान को ''पूर्ण

- **क्योंकि, अब ऑपरेशन ''सिन्दूर'' पर थरूर न केवल अपनी पार्टी से भिन्न मत प्रस्तुत कर रहे हैं, बल्कि, वो तर्क प्रस्तुत कर रहे हैं, भाजपा सरकार की ओर से, जो स्वयम् मोदी या उनके अफसर या उनके पार्टी के नेता प्रस्तुत करने से हिचकिचाते हैं।**
- **जब थरूर से पूछा गया क्या कि आप अब भाजपा ''जॉइन'' कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब तक किसी भी पार्टी का इतिहास, सोच, व मान्यताएं पूर्णतया अंगीकार नहीं कर लेते उस पार्टी को ''जॉइन'' करना गलत मानते हैं। पर वे, ''इंडिपैन्डैंट'' तो रह ही सकते हैं।**

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

जिंदा बम प्रकरणः हाईकोर्ट ने रिकॉर्ड मंगाया

जयपुर, 13 मई। राजस्थान हाईकोर्ट ने 13 मई, 2018 को शहर में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के बाद जिंदा मिले बम के मामले में विशेष न्यायालय से रिकॉर्ड तलब किया है। इसके साथ ही अदालत ने मामले में राज्य सरकार को भी नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। जस्टिस अवनीश झिंगन और जस्टिस भुवन गोयल की

- **याचिका में चार अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा को चुनौती दी।**

खंडपीठ ने यह आदेश अभियुक्त शाहबाज हुसैन की आपराधिक याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए। दूसरी ओर मामले के एक अन्य अभियुक्त, सरवर आजमी ने भी निचली अदालत के सजा के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दे दी है।

याचिका में अधिवक्ता फाहरुख अहमद ने बताया कि बम धमाकों के मूल मामले में विशेष न्यायालय ने याचिकाकर्ता को बरी कर दिया था। शेष

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

भारत-पाक युद्ध को अन्तर्राष्ट्रीय मीडिया में इतना कम स्थान/फोकस क्यों मिल रहा है

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 13 मई। आतंकी हमले, जवाबी हमले, ड्रोन स्ट्राइक और पलटवार, और फिर दोनों देशों के दावे, कि किसे कितना नुकसान हुआ, यह सब दक्षिण एशिया में सुर्खियों में हैं। लेकिन पश्चिमी मीडिया की प्रतिक्रिया काफी मौन और धीमी रही है। जब दो परमाणु शक्ति संपन्न देश टकराव के कगार पर हों, तो वैश्विक स्तर पर अधिक तीव्र प्रतिक्रिया की अपेक्षा की जाती है। इसके विपरीत, इन घटनाओं का कवरेज छुटपुट, यदाकदा और मध्यम रहा और यूक्रेन, गाज़ा या अमेरिका की राजनीति जैसे मुद्दों की छाया में कहीं दबा हुआ सा रहा, ऐसा क्यों?

इसका उत्तर भू-राजनीतिक प्राथमिकताओं, मीडिया की आर्थिक रणनीति और रिस्क नहीं लेने की संपादकीय मनोवृत्ति के जटिल जाल में छिपा है।

पहला कारण है, वृत्तांत थकावट (नैरेटिव फटीग)। पश्चिमी न्यूज़रूम पहले से ही यूक्रेन के युद्ध और गाज़ा की मानवीय त्रासदी जैसे उच्च-तीव्रता वाले वैश्विक संकटों से जूझ रहे हैं। ऐसे में दक्षिण एशिया की खबरें तब तक ध्यान में नहीं आतीं, जब तक कि वे किसी भयानक स्तर तक न पहुँच जाएं। नैरेटिव फटीग का अर्थ है कि सम्पादक और पत्रकार विश्वभर में व्याप्त हाई इन्टैन्सिटी संकटों को कवर करते-करते थक गए हैं। संपादकों और पत्रकारों की ऊर्जा और संसाधन सीमित हैं।

यूक्रेन पर रूस की चढ़ाई तथा गाज़ा का मानवीय संकट, जैसी ग्लोबल खबरों के कारण साउथ एशिया सहित अन्य क्षेत्रों को अक्सर कम कवरेज मिलता है। भारत-पाक प्रतिद्वंदिता को एक ''स्थायी क्षेत्रीय झगड़े'' के रूप में देखा जाता है, न कि किसी तात्कालिक वैश्विक संकट के रूप में। इस नज़रिए का सूक्ष्म खतरा यह है कि दक्षिण एशिया में परमाणु तनाव को सामान्य मान लिया गया है, जबकि स्थिति गंभीर होती जा रही है।

वास्तविक खतरा इस रवैये से पैदा होने वाली आत्मसंतुष्टि (कम्प्लैसन्सी) में निहित है। दक्षिण एशिया में परमाणु तनाव को सामान्य मानकर या अनदेखा करके दुनिया बढ़ते तनाव और संघर्ष के संकेतों को मिस कर सकती है, जिससे गलत अनुमान लगाने का संकट का खतरा बढ़ जाता है।

दूसरा कारण है, इस क्षेत्र की रिपोर्टिंग में चुनौतियाँ। संघर्ष क्षेत्रों, जैसे कि कश्मीर में पत्रकारों की पहुँच सीमित है। भारत और पाकिस्तान दोनों ही अपने-अपने पक्ष को आक्रामक रूप से प्रचारित करते हैं। स्वतंत्र सत्यापन की कमी के कारण संपादक किसी भी पक्ष के दावों को प्रमुखता देने से कतराते हैं। परिणामस्वरुप, इस तरह की खबरें सावधानी बरतते हुए लिखी जाती हैं और उन खबरों के आगे इन्हें उन्हें प्राथमिकता नहीं दी जाती, जिनकी पुष्टि की जा सकती है और जो आसानी से मिल जाती हैं।

इसके अलावा, पश्चिमी मीडिया अब ''पक्षपाती'' दिखने से बचना चाहता है। अगर भारत की सैन्य कार्यवाही को उजागर किया गया, तो मानवाधिकार संगठनों या पाकिस्तानी आलोचकों की आलोचना का सामना करना पड़ेगा। वहीं, अगर पाकिस्तान की उकसावे वाली भूमिका को उजागर किया गया, तो भारतीय समर्थकों की तीखी प्रतिक्रिया हो सकती है। ऐसे में ''संतुलन'' के नाम पर मीडिया एक हल्की और सतही रिपोर्टिंग का सहारा लेता है।

एक और कारक है, पाठकों व

- **जबकि, दोनों देश न्यूक्लियर हथियारों से सुसज्जित हैं, और किसी भी देश की नादानी/नासमझी/गैर जिम्मेदाराना सोच/एक्सीडैंट के विश्व के लिए भयानक व दर्दनाक (डैवस्टेटिंग) परिणाम हो सकते है।**
- **इन मीडिया की इस युद्ध के प्रति बे परवाह सोच व रवैये का विश्लेषण उतना ही जरूरी है, जितना इस युद्ध को विश्व युद्ध में परिवर्तित होने से रोकना।**

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'ऑपरेशन सिंदूर अब भारत का ''न्यू नॉर्मल'' है'

नयी दिल्ली, 13 मई। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मंगलवार सुबह सवेरे आदमपुर वायु सेना स्टेशन पहुंचे और वहां मौजूद वायुयौद्धाओं तथा अन्य जवानों से बातचीत की। पाकिस्तान ने इस वायु सेना स्टेशन पर लड़ाकू विमानों

- **आदमपुर वायु सेना स्टेशन पर सैनिकों के साथ मुलाकात में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। मोदी ने वायु रक्षा प्रणाली एस-400 के समक्ष जवानों को संबोधित कर पाकिस्तान के उस झूठ का पर्दाफाश कर दिया कि एस-400 नष्ट हो गई है।**

तथा ड्रोन से हमले का असफल प्रयास किया था। मोदी ने भारत की वायु रक्षा प्रणाली एस 400 के समक्ष जवानों को संबोधित कर पाकिस्तान के उस झूठ का

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

भारत-पाक युद्ध एक मध्यकालीन (मिडीवल टाइम्स) युद्ध है, जो, 21वीं शताब्दी में लड़ा जा रहा है

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 13 मई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस व्यक्ति की तरह दिखे, जो एक अदृश्य शत्रु से लड़ रहा हो।

उनका बयान भले ही देश के भीतर भी असर डालता हो, लेकिन मुख्य रूप से यह बाहरी दुनिया के लिए था। वे उस चीज़ के खिलाफ लड़ रहे थे, जिसका नाम नहीं लिया गया, लेकिन जिसे बहुत व्यापक रूप से फैलाया गया। वॉशिंगटन और अमेरिका में अफवाहें चल रही थीं कि भारत व पाक में अचानक हुआ युद्धिवराम अमेरिका ने इसलिए करवाया, क्योंकि उसकी खुफिया जानकारी के अनुसार, भारत की विनाशकारी वायु शक्ति से परेशान पाकिस्तान परमाणु हमला करने की योजना बना रहा था।

लेकिन इस पृष्ठभूमि में मुख्य मुद्दा यह है कि भारत में आधिकारिक रूप से युद्धिवराम घोषित होने से पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने उसकी घोषणा कर दी थी।

प्रधानमंत्री के बयान और भारत की परमाणु नीति पर उनके वक्तव्य को इसी संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए। पर्दे के पीछे क्या-क्या चल रहा था, वो असली बातें शायद वर्षों बाद सामने आएंगी, उम्मीद है कि तब ये आपसी संघर्ष केवल इतिहास बनकर रह जाएगा।

लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति का सार्वजनिक बयान और फिर टेलीविज़न पर इसे दोहराने से पूरा घटनाक्रम मज़ाक बनकर रह गया है। ऐसा लगता है, जैसे अमेरिका का सर्वोच्च पद एक बचकाने, अविवेकी, उद्दण्ड के हाथ में चला गया है, जो लगभग मूर्खता की सीमा पर है।

डॉनल्ड ट्रंप को भारत-पाक के बीच के संघर्ष की न तो समझ थी, न ही कोई जानकारी।

दुर्भाग्यवश, भारत एक बार फिर पाकिस्तान के साथ एक मध्ययुगीन संघर्ष में उलझ गया, पाकिस्तान, जो अपने पड़ोसी के खिलाफ एक ''पवित्र युद्ध'' लड़ रहा है।

इस संघर्ष की शुरुआत का भद्दा स्वरुप यह रहा, एक समूह ने निर्दोष लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी, और उनके निजी अंगों की जांच कर उनकी पहचान की। अगर भविष्य में कोई इतिहासकार इस संघर्ष को लिखेगा, तो शायद वह इसे ऐसे कहेगा ''युद्ध जिसका कारण.....है।'' अपराध की यह क्रूरता इतनी घिनौनी थी कि उसका उल्लेख करना भी कठिन है।

और इससे भी ज़्यादा अविश्वसनीय बात यह है कि इक्कीसवीं सदी का एक देश इन अपराधियों की रक्षा करने की कोशिश कर रहा है। वहीं, भारत की स्थिति देखिए, वह इस जघन्य अपराध के चारों ओर बने चक्रव्यूह में फंस गया। इन आतंकवादियों को सज़ा दिए बिना भारत पीछे नहीं हट सकता था और वो भी सबसे स्पष्ट और प्रभावशाली तरीक़े से।

इस संदर्भ में, डॉनल्ड ट्रंप की युद्धविराम पर टिप्पणी तो देखिए। उन्होंने कुछ इस तरह कहा: ''मैंने इन दोनों देशों के नेताओं से कहा, यह लड़ाई बंद करो। मैं तुम्हारे साथ व्यापार करूंगा। बहुत सारा व्यापार। लड़ाई बंद करो। अभी बंद करो। नहीं तो मैं व्यापार नहीं करूंगा। और उन्होंने लड़ाई बंद कर दी।''

क्या इससे ज़्यादा हास्यास्पद कुछ हो सकता है? एक ''पवित्र युद्ध'' को व्यापार के प्रस्ताव से रोक रहे हैं। यह एक मानसिकता का संघर्ष है, वह मानसिकता, जिसे कुछ समय पहले पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने व्यक्त किया था, जिसे ''मुल्ला मुनीर'' के नाम से जाना जाता है, जो उसके लिए सटीक नाम है।

इस मानसिकता को संबोधित कैसे किया जाए? यह जिहादी मानसिकता है। इसका इलाज किसी युद्धक्षेत्र में नहीं, बल्कि तब हो सकता है, जब किसी देश की मानसिकता को एक मनोचिकित्सक के पास ले जाकर इलाज कराया जाए या फिर जब तक उस मानसिकता को शारीरिक रूप से पूरी तरह नष्ट न कर दिया जाए।

यह वही नैतिक संघर्ष है, जिसका ज़िक्र अर्नेस्ट हेमिंग्वे ने स्पैनिश गृहयुद्ध पर अपने उपन्यासों में किया है। यही बौद्धिक टकराव विलियम फॉकनर के उपन्यासों में भी झलकता है।

अब सोचिए, डॉनल्ड ट्रंप का चीन के साथ क्या झगड़ा है? के अक्सर चीन के साथ व्यापार असंतुलन को लेकर झुंझलाते रहते हैं, कहते हैं कि चीन ने अमेरिका की तकनीक और शोध चुरा लिया, चीन ने वैश्विक व्यापार व्यवस्था का दुरुपयोग कर अमेरिका की निर्माण शक्ति को बर्बाद कर दिया।

इन्हीं अमेरिकी संसाधनों और धन से चीन ने आधुनिक हथियारों का भंडार खड़ा किया है - परमाणु हथियार, हाइपरसॉनिक मिसाइलें, नौसैनिक

- **पर, त्रासदी यह है कि यह ''मिडीवल वॉर'', तीर-कमानों, तलवारों व भालों से नहीं, बल्कि, 21वीं सदी के खतरनाक व भयानक हथियारों से (न्यूक्लियर बम) मिसाइल व ड्रोन से लड़ा जा रहा है।**
- **प्र.मंत्री मोदी की विडम्बना है कि वे एक अदृश्य शत्रु से लड़ रहे हैं, वॉशिंगटन व पाकिस्तान की अफवाह गढ़ने वाली एजेन्सियों से, जो टी.वी. व सोशल मीडिया का जमकर उपयोग करते हैं, पर सामने नहीं आते।**

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा के लिए राज्य सरकार क्या कर रही है

जयपुर, 13 मई। राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा को लेकर क्या कार्रवाई की गई है। इसके साथ ही अदालत ने सुरक्षा को लेकर लगाए गए सीसीटीवी कैमरों की खरीद को लेकर भी राज्य सरकार से जानकारी मांगी। राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस मुकेश राजपुरोहित ने यह आदेश मामले में लिए गए स्वप्रेरित प्रसंज्ञान पर सुनवाई करते हुए दिए। अदालत ने मौखिक रूप से कहा कि हम राज्य सरकार पर दबाव डालकर न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा नहीं चाहते, लेकिन न्यायिक अधिकारियों को अपनी सुरक्षा को लेकर किसी तरह का डर नहीं होना चाहिए।

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की

- **हाईकोर्ट ने इस संबंध में की जा रही कार्यवाही का ब्यौरा पेश करने के निर्देश दिये।**

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

CMYK